भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 112
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

भारत में बेरोजगारी की दर

112. डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की हाल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय युवाओं की बेरोजगारी दर वयस्कों की तुलना में अधिक है और पिछले कई दशकों से बढ़ रही है, जो 2000 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 6.2 प्रतिशत हो गई, फिर 2018 में तीन गुना बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत हो गई और 2020 में लगभग 15.1 प्रतिशत तक पहुंच गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), बड़ी कंपनियों, स्टार्टअप्स, एनजीओ और सरकारी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विश्वविद्यालय-उद्योग संबंधों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को बढ़ाकर रोजगार सृजित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ साझेदारी में मानव विकास संस्थान (आईएचडी) द्वारा तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, दो डेटा सेटों, रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) 2000 और 2012 पर आधारित है और 2018 से 2022 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है।

"कार्यबल परिवर्तन और रोजगार" पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पीएलएफएस सर्वेक्षण एक अलग नमूना ढांचे पर आधारित हैं और रोजगार पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (कन्नन और खान 2022) की तुलना में एक अलग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। इस वजह से, एनएसएसओ सर्वेक्षणों से उपलब्ध रोजगार और बेरोजगारी पर समय श्रृंखला डेटा, पीएलएफएस आंकड़े के साथ तुलनीय नहीं है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहित अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

(% में)

वर्ष	**यूआर**
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4
2022-23	10.0

स्रोत: पीएलएफएस

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****